

VII अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्यों के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण: -

प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान	नागरिकों को चुनाव लड़ने का एवं मत देने का अधिकार
नगरपालिका में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान	नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चयनीत प्रतिनिधियों द्वारा होता है ।
नगरपालिका में स्थायी समिति का प्रावधान धारा (Sec 50)	नगरपालिका में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है । इन समितियों का गठन, निगम/परिषाद/बोर्ड के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से परित संकल्प द्वारा किया जाएगा । समिति के कुल सदस्यों की संख्या नगरपालिका द्वारा तय की जाएगी पर समिति में अधिकतम सात पार्शाद होंगें ।
नगर परिषाद की सामान्य एवं विशेषा बैठक	नगर पालिका की बैठक एवं गणपूर्ति (कोरम) नगर पालिका की बैठक (धारा 28) महीने में कम से कम एक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, सदस्यों की कुल संख्या के आधे द्वारा हस्ताक्षरित अपने पत्र की तारीख के दस दिन की अवधि के भीतर साधारण या विशेषा बैठक बुलाएगा । अपेक्षा पत्र में बैठक का उद्देश्य अवश्य लिखा हो ।

यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्धारित अवधि में बैठक बुलाने में असमर्थ रहे तो हस्ताक्षर करने वाले सदस्य बैठक बुलाने के लिए उपमण्डल अधिकारी (सिविल) से प्रार्थना कर सकते हैं ।

गणपूर्ति (कोरम) (धारा 30)

नगर पालिका की कुल सदस्यों की संख्या का आधा ।

नगरपालिका बैठक में विपेश कार्य संपादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कुल सदस्यों (आसीन)की आधी (1/2) संख्या है ।

किसी नगरपालिका की सामान्य बैठक में कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति नगरपालिका के सदस्यों की ऐसी संख्या या उनका ऐसा अनुपात होगी जो उप विधियों द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाए, किन्तु तीन से कम नहीं होगी

नगरपालिका की बैठक में कोरम पूरा नहीं होने पर सभापति बैठक को अगली उपयुक्त अवधि के लिए स्थगित कर देगा । लेकिन अगली बैठक में वे सभी कार्य पूरे किए जाएंगे चाहे कोरम पूरा हो अथवा नहीं

बैठक की अध्यक्षता (धारा 31)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा चुना

गया कोई भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर सकता है ।

प्रस्ताव पारित करना (धारा 32)

नगरपालिका के सारे प्रस्ताव बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होंगे । मतों की संख्या बराबर होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन; चतुर्विध प्रमाणपत्र

और प्रकाशन (धारा 32)

प्रत्येक बैठक के कार्यवत तैयार किए जाएंगे, वही रजिस्टर में लिखे जाएंगे तथा सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

कार्यवाही ऐसी भाषा में लिखी एवं प्रकाशित की जाएगी जो सरकार निर्दिष्ट करे ।

प्रत्येक पारित संकल्प की एक कापी, बैठक की तारीख से 30 दिन के अन्दर उपायुक्त एवं निदेशक को भोजी जाएगी ।

निदेशक की शक्तियां (धारा 35)

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की सभी या जो उचित समझें शक्तियां दे सकेंगी ।

नगरपालिका परिषद की
तीन
स्थायी/कार्यकारी/प्रशासन
समिति/अन्य समिति की
बैठक

सदस्यों के साथ बैठकें कम से कम
महीने में एक बार होनी चाहिए ।
50 प्रतिशत सदस्यों का प्रतिनिधित्व
फोरम पूरा करने के लिए जरूरी है
।

समिति की बैठकें में अपनाई जाने
वाली प्रक्रिया: -

नगरपालिका की किसी समिति की
बैठकों का संचालन ऐसी प्रक्रिया के
अनुसार होगा जो विधि की जाये ।

यदि किसी समिति का अध्यक्ष पन्द्रह
दिन से अधिक की कालावधि के
लिए नगरपालिका से अनुपस्थित
रहता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष
उसकी अनुपस्थिति में समिति की
बैठक बुला सकेगा ।

समितियाँ जैसा वे उचित समझें
अपनी बैठकें कर सकेंगी और उन्हें
स्थगित कर सकेंगी लेकिन समिति
का अध्यक्ष जब कभी वह ठीक
समझें ऐसी समिति की विशेषा बैठक
बुला सकेगा तथा बोर्ड के अध्यक्ष के
या समिति के कम से कम दो
सदस्यों के लिखित निवेदन के
प्रस्तुतीकरण से दो दिन से अधिक
बाद की न हो ऐसी बैठक बुलायेगा

। समिति की बैठक मे कोई कार्य तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसमें समिति के आधे सदस्य उपस्थित न हो ।

प्रत्येक सदस्य के अधिकार और विशेषाधिकार: -

कोई भी सदस्य किसी नगरपालिका कार्य के निशपादन में की गयी किसी उपेक्षा नगरपालिका सम्पति की किसी बरबादी या किसी परिक्षेत्र की आवश्यकताओं की और ऐसे सुधार का जिसे वह वांछनीय समझे सुझाव भी दे सकेगा ।

प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अध्याधीन रहते हुए अध्यक्ष से प्रश्न पूछने तथा नगरपालिका प्रशासन से संबंधित मामलों पर संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष को सम्यक नोटिस देने के पश्चात नगरपालिका के कार्यालय में बोर्ड के अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा परन्तु अध्यक्ष लिखित में दिये गये कारणों से ऐसे निरीक्षण का निरोध कर सकेगा ।

नगरपालिका की नियम बनाने की शक्ति

नियम बनाने की प्रक्रिया में यह धारा मान्य है अन्य मामलों में यदि नियमों का प्रकाशन नैसर्गिक न्याय

के सिद्धान्तों के अनुकूल होगा एवं इसके निम्न चरण होंगे-

उन सभी व्यक्तियों नियम के प्रारूप भेजना तथा उसका प्रकाशन ।

निश्चित अवधि के भीतर आपेक्ष निमन्त्रित करते हुए सूचना (नोटिस)

प्राप्त हुए आक्षेपों ; एतराजोद्ध पर विचार एवं इसे अंतिम स्वरूप ।

राज्य सरकार की स्वीकृति ।

नियमों को किसी दूसरे तरीके से व्यापक रूप से

प्रकाशित (प्रचारित) करना होगा -

नियमों तथा उपविधियों को जनता के द्वारा निरीक्षण के लिए

नगरपालिका कार्यालय में खुला

रखा जाएगा, ताकि कार्यालय समय के भीतर उनका निरीक्षण किया जा

सके और इन नियमों तथा उप विधियों को मुद्रित करवाकर

लागत-मूल्य पर बेचा जाएगा इस

प्रकार जनता को इन नियमों और उपविधियों से अवगत कराया जावेगा

। ये उपबंध निदेशात्मक है, न कि आज्ञापक । इनका पालन न करने

से ऐसे नियम और उपविधियाँ अवैध नहीं होगी ।

उप विधियाँ बनाने की प्रक्रिया के

चरण-

बायलॉज

नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर रखे गए/किराए के लिए चल रहे वाहनो/रिाए के लिए रखे गए पशुओ/चालको के लिए लाइसेन्स तथा इसकी फीस/शर्ते नियत करेगी । इसके अलावा पहियों के टायरों के लिए नयूनतम चौडाई और ब्यास निर्धारण के लिए उपबन्ध करेगी

किराए पर लिए गए पशुओं/व्यक्तियो की सेवाओं के लिए गाडी या सवारी के लिए नगरपालिका मूल्य सीमित करेगी ।

जन्म/विवाह/मृत्यु के उचित पंजीकरण जनगणना के लिए उपबन्ध करेगी ।

उन व्यक्तियो की संख्या नियत/परिवर्तन करेगी, जो किसी ऐसे निर्माण या उसके किसी भाग का कब्जा करता हो /निवास के लिए किराए पर दिया जाता है/ एक से अधिक परिवार के सदस्यों द्वारा रहने के लिए कब्जा किया हुआ है अथवा ऐसे भीड वाले बजार क्षेत्रो मे स्थित है,जैसे उपविधि में निर्दिशत किया जाए और निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेगी

निमाणों का पंजीकरण/निरीक्षण

होटलों/किराए के मकान, भवन का लाईसेन्स और ऐसी लाइसेन्सों के

लिए फीस, शर्तें दी / रद्द की जा सकती है ।

ऐसे निर्माणों में स्वच्छता/हवा के संचार को बढ़ावा ।

ऐसे निर्माणों में फैल रही संक्रामक बीमारी/ कूड़ाकरकट/गन्दगी/ मलजल का हटाना/ निपटारा करना ।

होटल/सराय/यात्री भवन और सराय के मालिकों तथा आवासियों क्लबों के सचिवों की दशा में आगन्तुकों का पंजीकरण ऐसे प्रारूप में रखना जैसे नगरपालिका विहित करे ।

निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेगी: -

धारा 125 के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थानों/शिविर/कांजी हाउस(Slaughter House)/सराय/बेकरियों/सोडा वाटर कारखानों/बर्फ कारखानों/धोबी घाटों/खाद्यान्न गोदामों/रसायनों की दुकानों/वधशालाओं का निरीक्षण और नियंत्रण ।

मंडियों और स्टालों का निरीक्षण और विनियमन/मूल्य सूची तैयार करना/प्रदर्शित करना/फीस/ किराए और अन्य प्रभार नियत करना

नगरपालिका क्षेत्र के भीतर/उसके नियंत्रण में मेले/ औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाना और धारा 201 के अधीन फीस का इक्टठा करना ।

कब्रिस्तान/शमशान के प्रयोगों और प्रबन्ध का नियंत्रण ।

नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर सार्वजनिक तालाबों कुओं/अन्य स्रोतों का जल उपलब्ध कराना/निरीक्षण/नियंत्रण/प्रदूषण से सुरक्षा ।

थियटरो/मनोरंजन के स्थानों का अनुज्ञापन निरीक्षण और नियंत्रण ।

ऐसी कहलों का निरीक्षण /नियंत्रण जिनमे ऐसे नहर से जल सप्लाई किया जाता हो जिस पर या तो उतरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम 1873 या हिमाचल प्रदेश लघु नहर अधिनियम 1976 लागू होता है । नगरपालिका क्षेत्र मे निर्माण या भूमि के स्वामी द्वारा जो नगरपालिका क्षेत्र मे निवासी नही है, नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर /निकट रहने वाले व्यक्तियों की इस अधिनियम/नियमों के प्रयोजनो में से सभी या किसी के लिए एजेन्ट के रूप मे कार्य करने के लिए नियुक्ति की अपेक्षा नियंत्रण करेगी ।

नगर पालिका वित्तीय नियंत्रण और लेखा-परीक्षा

वित्तीय नियन्त्रण और लेखा परीक्षा (धारा 249)

वित लेखा परीक्षण एवं योजना समिति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक

वित्त वर्षा के लिए नगरपालिका के आय-व्यय के बजट तथा वास्तविक व प्रत्याक्षित आय व्यय का पूर्ण लेखा जोखा तैयार करेगी

इस कार्य हेतु नगरपालिका की बैठक फरवरी के प्रथम दिवस से मार्च के दसवें दिन के बीच आयोजित की जानी चाहिए ।

नगरपालिका की बैठक में पारित बजट, उपायुक्त के माध्यम से निदेशक को, तय तारीख से पूर्व भेजा जाएगा ।

यादि नगरपालिका उपरलिखित तारीख को या उससे पूर्व बजट (प्रकाशित) को मंजूरी देने में असफल रहती है तो नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी/सचिव बजट अनुमानित(Budget Estimation) को उपायुक्त के माध्यम से निदेशक को भेजेगे ।

अनुपूरक बजट (धारा 251)

नगरपालिका द्वारा, आवश्यकतानुसार अनुपूरक बजट तैयार व प्रस्तुत किया जा सकता और उसे उपायुक्त के माध्यम से निदेशक को भेजा जाएगा । ऐसे प्रत्येक बजट पर नगरपालिका विचार करेगी और अनुमोदित करेगी ।

लेखों की लेख परीक्षा (धारा 255)

नगरपालिका निधि के लेखों की

लेखा परीक्षा, स्वतंत्र लेखा परीक्षा अभिकरण द्वारा की जाएगी। ऐसे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए नगरपालिका के सभी लेखाओं और अन्य अभिलेखों तक पहुंच होगी।

आडिट ऐजेन्सी लेखा परीक्षा के समाप्ति के एक महीने के भीतर रिपोर्ट की एक कॉपी नगरपालिका को भेजेगी।

रिपोर्ट की प्राप्ति पर नगरपालिका उस पर विचार करेगी और फिर उसकी उतनी प्रतियां जितनी राज्य सरकार चाहे, बिना किसी देरी के उपायुक्त और निदेशक के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार प्राप्त की गई रिपोर्ट का विधानसभा के समक्ष रखेगी।

नियंत्रण

उपायुक्त द्वारा नियंत्रण(धारा 262)

उपायुक्त या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार सतत कोई व्यक्ति नगरपालिका की किसी स्थाई सम्पत्ति पर या उसके नियंत्रण में चल रहे किसी कार्य पर प्रवेश निरीक्षण, सर्वेक्षण करवा सकता है।

कार्यकारी अधिकारी/सचिव को संबन्धित लिखित आदेश द्वारा नगरपालिका अपने नियंत्रण में निर्देशात अवधि के भीतर किसी

रिपोर्ट का विवरण और ऐसी कार्यवाहियों/कर्तव्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मंगवाने/प्रस्तुत करने की आपेक्षा कर सकता है उसका निरीक्षण कर सकता है ।

उपायुक्त ऐसी किसी नगरपालिका की कार्यवाहियों या कर्तव्यों के बारे में ऐसी टिप्पणियां अभिलिखित कर सकता है जिन्हे वह ऐसी नगरपालिका के विचारार्थ प्रस्तुत करना उचित समझे ।

प्रत्येक नगरपालिका उपायुक्त को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिनके लिए राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

MC-PAN